

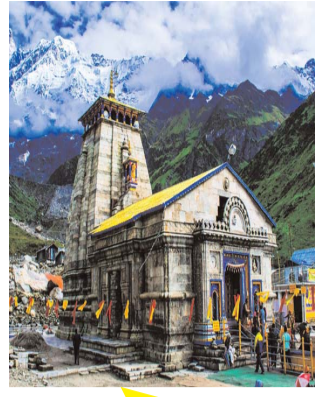


हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

निर्भीक, निष्पक्ष, सच का प्रवाह



वर्ष:5 अंक:148 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, गुरुवार, 04 जून 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण

पथ प्रवाह, ऋषिकेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण कर चारधाम यात्रा एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं से यात्रा का फीडबैक भी लिया।

श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए न करना पड़े इंतजार

मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के लिए की गई पंजीकरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए की श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने स्वास्थ्य जांच केंद्रों का निरीक्षण कर यात्रियों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने को बात कही। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने ट्रांजिट कैंप में अतिरिक्त कुलर लगाने तथा पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वाच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले



श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी संवाद किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का 'अतिथि देवो भवः' की भावना के साथ स्वागत करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

यात्रियों ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट

कैंप में मौजूद श्रद्धालुओं से भी संवाद कर यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार सहित विभिन्न राज्यों से आए यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। श्रद्धालुओं ने पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, आवास एवं अन्य सुविधाओं को संतोषजनक बताया। कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जाना और उन्हें सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की

शुभकामनाएं दीं।

ट्रांजिट कैंप में धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की भी सराहना

ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के लिए एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रामायण एवं महाभारत के प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रतीक्षा के दौरान उन्हें आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश से आई कामिनी ने कहा कि 'वह गुरुवार से अपनी चार धाम यात्रा शुरू करेंगी। आज सुबह उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वह सुबह से ही ट्रांसिट कैंप में

बैठी हैं, वहां कूलर, पंखे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है उन्होंने बताया साथ ही टीवी में रामायण चलने से उनका समय भी अच्छा बीत रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए शुभम ने बताया कि 'वो अपने 3 दोस्तों के साथ चार धाम यात्रा से वापस ऋषिकेश लौटे आए हैं, आज सुबह से ही वह ट्रांजिट कैंप में हैं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू भी ट्रांसिट कैंप से की थी, जहां उन्हें सुविधा इतनी अच्छे लगी की वह लौटते समय भी यहां ठहरने के लिए आए हैं'। मध्य प्रदेश से आए ओमप्रकाश ने बताया कि वह भी सुबह ही ट्रांजिट कैंप पहुंचे हैं और आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिट कैंप में ही अपना भोजन किया और स्वास्थ्य जांच करवाई। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की।

ट्रांजिट कैंप में लंगर सेवा के साथ स्थानीय उत्पादों को मिला बढ़ावा

ट्रांजिट कैंप परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर लंगर एवं निःशुल्क भोजन-पानी की व्यवस्था की जा रही है। एक ओर जहाँ स्वयंसेवकों द्वारा यात्रियों को भोजन की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कैंप परिसर में स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी की जा रही है। इन स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद एवं स्वरोजगार से जुड़े सामान यात्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

12 वर्षों में मोदी सरकार ने देश को दी नई दिशा: त्रिवेन्द्र सिंह रावत



पथ प्रवाह, हरिद्वार।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी अनेक प्रभावी कदम उठाए।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की एकता और अखंडता को नई मजबूती मिली है और भारत का वैश्विक स्तर पर गौरव बढ़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से

आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का आधार उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह और मेहनत का ही परिणाम है कि आज 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और पार्टी निरंतर विस्तार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त हो रहा है।

सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि पार्टी द्वारा लगातार संतों, सामाजिक संगठनों और आम जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे भाजपा को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया 29.78 करोड़ की 3 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

पथ प्रवाह, ऋषिकेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को होटल नटराज, ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति बैठक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 29.78 करोड़ की 3 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 23.15 करोड़ की 1 योजना का लोकार्पण एवं 6.63 करोड़ की 2 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न शहरों के मेयर का स्वागत करते हुए कहा कि सभी मेयर अपने शहर के प्रथम नागरिक और शहरवासियों की आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास के भी प्रतिनिधि हैं। आपके निर्णय का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा हमारे देश की आत्मा गाँवों में बसती है, तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएँ और उनके भविष्य की संभावनाएँ शहरों में आकार लेती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को उत्तराखंड में बिताया है। वे उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र से भली भाँति परिचित हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष चार धाम यात्रा में अब तक कुल 45 दिनों में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की है, जो एक



नया रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम, सुरक्षित हो। उन्होंने कहा पहले, आदि कैलाश में 500 लोग आते थे, इस वर्ष यात्रा शुरू होने से अब तक प्रति दिन करीब 1000 लोग आदि कैलाश पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया मां पूर्णागिरि मंदिर में भी 24 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। बीते चार सालों में 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों में साफ-सफाई की नई संस्कृति विकसित हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का घर का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी

वालों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के शहरों के विकास को नई गति दी जा रही है। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य में निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारम्भ की है। स्थानीय निकायों में श्वाणों की बढ़ती संख्या की रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत की है। हरित क्षेत्रों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर, दुनिया के समक्ष देश की वास्तविक छवि भी प्रस्तुत करते हैं। शहर सुव्यवस्थित, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित होंगे तो भारत की छवि भी सशक्त, समृद्ध और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी।

हरिद्वार में शहर से लेकर देहात तक अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में नगर निगम क्षेत्र से लेकर विभिन्न तहसीलों तक सरकारी भूमि, सड़कों, फुटपाथों और नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए।

नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ललतारौ पुल से अपर रोड तक अभियान चलाकर मार्ग और नालियों पर किए गए 80 से अधिक अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। अभियान के दौरान कुछ व्यापारियों द्वारा विरोध का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई।

नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में नाली के ऊपर अथवा



नाली की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का सामान, निर्माण सामग्री अथवा व्यावसायिक सामग्री रखी जाती है तो उसे तत्काल जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बार-बार अतिक्रमण किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर देकर विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की

जाएगी।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट हरगिरी, उपजिलाधिकार योगेश मेहरा, उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, सफाई निरीक्षक धीरेन्द्र सेमवाल, पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम हरिद्वार की टीम उपस्थित रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि

जनहित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

रुड़की में कलियर से लेकर धनोरी तक अतिक्रमण हटाया

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसील प्रशासन, पुलिस द्वारा कलियर से लेकर धनोरी तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण, जिसमें सड़क किनारे लगाए गए लगभग 200 से अधिक अवैध रूप से संचालित हो रही रेहड़ी, ठेली एवं खोखे को भी हटाया गया तथा 03 स्थाई अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।

लक्सर बाजार से भी हटाया गया अतिक्रमण

उप जिलाधिकारी लक्सर अनिल शुक्ला ने बताया कि लक्सर बाजार में सड़क किनारे, फुटपाथ एवं नालियों के ऊपर

किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन की टीम द्वारा हटाया गया तथा इस दौरान 05 लोगों के चालान भी किए गए तथा सभी लोगों को चेतावनी दी गई कि सड़क किनारे, फुटपाथ एवं नालियों के ऊपर किसी भी दशा में अतिक्रमण न किया जाए।

तहसील भगवानपुर में आज चलेगा अभियान

उप जिलाधिकारी भगवानपुर देवेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा भगवानपुर तहसील क्षेत्रांतर्गत किए गए अतिक्रमण को स्वयं से हटाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया कि यदि सड़क, नालियों एवं फुटपाथ से अतिक्रमण को स्वयं नहीं हटाया गया तो तहसील प्रशासन द्वारा आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा।

एक नजर

योगाचार्य से 70 हजार की ठगी, होम स्टे दिलाने के नाम पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ में कार्यरत एक योगाचार्य को होम स्टे दिलाने के नाम पर 70 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह के अनुसार बिहार के सुपौल जनपद के ग्राम हरिहरपुर निवासी राजीव कुमार रंजन ने शिकायत दर्ज कराई कि वह हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में योगाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हरिद्वार में रहने के लिए उन्हें किराये पर होम स्टे की आवश्यकता थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात रुड़की तहसील के ग्राम बेलड़ा निवासी सोनू पाल से हुई। आरोप है कि सोनू पाल ने अपनी माता रविता के नाम पर शांताशह-सहदेवपुर रोड स्थित एक होम स्टे किराये पर दिलाने का प्रस्ताव दिया। 15 जनवरी 2025 को किरायानामा तैयार कराने के दौरान आरोपी ने अपनी जरूरत बताते हुए 70 हजार रुपये अग्रिम देने को कहा और भरोसा दिलाया कि यह राशि किराये में समायोजित कर दी जाएगी। विश्वास में आकर योगाचार्य ने आरोपी के खाते में ऑनलाइन 70 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और होम स्टे उपलब्ध नहीं कराया। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।

महात्मा गांधी के विचारों और तकनीक के संगम से शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत: विजय गोयल

शिक्षा में तकनीक का समावेश समय की मांग है- संजय जायसवाल

नई दिल्ली। शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समावेश और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा चंपारण के सिरसिया अड्डा और कुमारबाग स्थित बुनियादी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा हेतु प्रोजेक्टरों का वितरण किया गया। तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल को प्रोजेक्टर सौंपे। इसका उद्देश्य विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा संसाधनों से जोड़ना है। इस अवसर पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने गांधी स्मृति द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रोजेक्टर और डिजिटल शिक्षण सामग्री से विद्यालयों में पढ़ाई अधिक प्रभावी, रोचक और सहभागितापूर्ण बनेगी। जायसवाल ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की है। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के आत्मविश्वास और ज्ञानवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का आभार प्रकट किया।

विजय गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी सोच को वर्तमान समय की तकनीकी आवश्यकताओं के साथ जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्वस्तरीय शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बना सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधि अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय, रिटैनिंग तथा विभिन्न न्यायालयों में पेशी की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले का लाभ जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक और उप शासकीय अधिवक्ता सहित नामित वकीलों तथा विशेष अधिवक्ताओं को मिलेगा।

जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक राज्य सरकार

बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला करने वाला 10 दिन बाद गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर लतीफपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खेतों के बीच हुई इस वारदात के कारण मामला पूरी तरह ब्लाईड था, लेकिन पुलिस की मैनुअल पुलिसिंग, तकनीकी जांच और लगातार 10 दिनों की मेहनत ने आखिरकार आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के अनुसार 23 मई को गांव से दूर खेतों में एक बुजुर्ग महिला अचेत अवस्था में पड़ी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला को देहरादून स्थित दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़िता के भतीजे संजय कुमार की तहरीर पर कोतवाली भगवानपुर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि घटनास्थल खेतों के बीच था और आसपास न तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी, इसलिए आरोपी तक



पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया तथा करीब 250 सदिध लोगों से पूछताछ की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस की जांच रज्जाक नामक व्यक्ति पर जाकर रुकी। 2 जून को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह पीड़ित महिला से घास और दरांती मांगता था, लेकिन महिला ने कई बार उसकी मांग पूरी नहीं की। इसी बात को लेकर वह उससे नाराज था। घटना वाले दिन वह मोटरसाइकिल से खेतों की ओर गया और भांग मिलाकर बीड़ी

पीने के बाद गुस्से में महिला पर हमला कर दिया। आरोपित ने पहले आम के पेड़ के नीचे बैठी महिला को डंडे से पीटा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसने महिला के चेहरे और मुंह पर कई मुक्के मारे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के मुंह से खून निकलने और उसके न बोलने पर आरोपी ने उसे मृत समझ लिया तथा ईश्वर के खेत में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित रज्जाक पुत्र लालदीन निवासी खुब्बनपुर, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपित का चालान कर दिया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने की आकांक्षी जनपद और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने नीति आयोग के अंतर्गत संचालित आकांक्षी जनपद कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सर्वप्रथम आकांक्षी जनपद कार्यक्रम हरिद्वार के अंतर्गत स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन संकेतकों में संतुष्टि की स्थिति प्राप्त हुई है, उनके लिए संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही अवशेष संकेतकों में शत-प्रतिशत संतुष्टि प्राप्त करने हेतु विभागों को और अधिक प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए गए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम बहादुराबाद की



समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी विभाग को अपने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हुए संकेतकों की प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों को

संकेतकों से संबंधित नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों एवं प्रभावी पहलों के दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा ताकि अधिक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

10 साल बाद पलटा चुनावी नतीजा, मद्रास हाई कोर्ट ने एम. अप्पावु को घोषित किया 2016 का विजेता

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ा एक दशक पुराना चुनावी विवाद आखिरकार न्यायिक फैसले के साथ समाप्त हो गया। मद्रास हाई कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कणम (डीएमके) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु को वर्ष 2016 के राधापुरम विधानसभा चुनाव का वैध विजेता घोषित कर दिया है। अदालत ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणम (एआईएडीएमके)

उम्मीदवार आई. एस. इनबादुरै की जीत को अवैध करार दिया। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 2016 से 2021 तक के विधानसभा कार्यकाल के लिए एम. अप्पावु ही राधापुरम के वास्तविक विधायक थे। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी अभिलेखों में एम. अप्पावु का नाम विधायक के रूप में दर्ज किया जाए और उन्हें उस अवधि

से जुड़े सभी वेतन, भत्ते एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं। यह विवाद वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था, जब तिरुनेलवेली जिले की राधापुरम सीट पर आई. एस. इनबादुरै को मात्र 49 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। इसके बाद एम. अप्पावु ने पोस्टल बैलेट और मतगणना के अंतिम चरणों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया।



10 साल से संविदा में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को करें नियमित: भगवत प्रसाद मकवाना

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग भगवत प्रसाद मकवाना बुधवार को जनपद भ्रमण पर पहुंचे। यहां सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं सफाई कर्मचारियों के समस्याओं को लेकर सीसीआर सभागार, हरिद्वार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण मित्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें हर हाल में लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों का किसी भी तरह से कोई उत्पीड़न न किया जाए तथा सभी कार्मिकों



को समय से उनका वेतन का भुगतान किया जाए एवं जो कार्मिक विगत 10 वर्षों से संविदा /आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं सफाई कार्मिकों को तत्काल नियमित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि

सफाई कर्मचारियों को जो भी वर्दी एवं सफाई उपकरण दिए जाते हैं उन्हें नियमानुसार सभी को उपलब्ध कराए जाए तथा मृतक आश्रितों को 15 दिन के भीतर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन सफाई कर्मचारियों के आयुष्मान एवं

गोल्डन कार्ड नहीं बनाए गए हैं उनके लिए शिविर आयोजित किए जाए तथा समय समय पर सभी सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परिक्षण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने जिला चिकित्सालय/मेला चिकित्सालय में ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों का शासन द्वारा निर्धारित किया गया वेतन 13058 रुपये उपलब्ध कराया जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को 7300 रुपए दिया गया है, जब की माह अप्रैल का वेतन मई में उपलब्ध कराया गया है, वह 8800 दिया गया है, जिसपर उपाध्यक्ष द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्लॉक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए तथा सफाई कर्मचारी हेतु टेंडर प्रक्रिया दोबारा कराए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि नमस्ते योजना के तहत जो भी सफाई कर्मचारी

पंजीकृत किए गए हैं उन्हें संचालित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों का पुनः सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने उपाध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

बैठक में पूनम वाल्मीकि, सुरेंद्र तेश्वर, सुनील राजौर, सपना वाल्मीकि, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी, सफाई यूनियन के अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

एक नजर

चारधाम यात्रा के लिए 8082 यात्रियों ने कराया पंजीकरण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में बनाए गए यात्री पंजीकरण केंद्र में चारधाम यात्रा के लिए 8082 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया। इनमें यमुनोत्री धाम के लिए 1492, गंगोत्री धाम के लिए 1471, केदारनाथ धाम के लिए 2403, बद्रीनाथ धाम के लिए 2671 और हेमकुंड साहिब के लिए 45 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया। इस तरह एक दिन में विभिन्न राज्यों से आए 8082 यात्रियों द्वारा चारधाम के लिए अपना पंजीकरण कराया गया। ऋषिकुल मैदान यात्री पंजीकरण केंद्र से अब तक कुल 3 लाख 69 हजार 9 सौ 15 यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

नशीले कैप्सूल समेत आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



पथ प्रवाह, हरिद्वार। थाना सिडकुल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि मेडिकल स्टोर स्वामी फरार हो गया। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एएसपी के नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देशों पर कोतवाली सिडकुल पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर महादेव मेडिकल स्टोर ब्रह्मपुरी रावली महदूद पर छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने 101 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। नशीले कैप्सूल बरामद होने पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद सागर पुत्र शिवकुमार निवासी सहारनपुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर स्वामी फरार हो गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अजय शाह, एएसआई विकास रावत, हेडकांस्टेबल सुनील सैनी, कांस्टेबल रोहित शामिल रहे।

युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मांगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान का इस्तीफा



पथ प्रवाह, हरिद्वार। नीट पेपर लीक और सीबीएसई घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बहादुराबाद स्थित पृथ्वीराज चौहान चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्य चौहान ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बार-बार पेपर लीक से बच्चों और उनके अभिभावकों को आर्थिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी में बच्चों के साथ पूरा परिवार भी शामिल होता है। ऐसे में पेपर लीक से परिवार पर क्या बीतती होगी। इसका अंदाजा भाजपा सरकार को नहीं है। नीट के बाद सीबीएसई में भी घोटाला यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार देश को चलाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा उनसे इस्तीफा लेने की जगह उनको बचा रही है। यह देश के साथ धोखा है। युवा कांग्रेस बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर मोमिन, हर्ष चौहान, कुलदीप, पीयूष चौहान, सादाब, आनंद शर्मा, करीम हसन, अमजद, मोहित, विक्रम, अकरम, जमशेद, अमित, आशीष आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

ज्वैलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना?

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने एक ज्वैलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी अंबर तालाब स्थित खन्ना ज्वैलर्स में देर रात अज्ञात चोरों ने संधे लगाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकान से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषणों के साथ नकदी भी अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया है कि आधी रात के समय सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार में सवार होकर कुछ लोग दुकान के बाहर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दुकान का शटर और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोपियों ने करीब एक घंटे तक दुकान के भीतर रहकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया



और फिर एक-एक कर मौके से फरार हो गए। बुधवार सुबह चोरी की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में दिखाई दे रहे सदिग्धों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उनके आने-जाने के रूट और वाहन की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सदिग्धों की पहचान की जा रही है तथा घटना के शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।

उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने जनसंवाद शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड सरकार के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) देशराज कर्णवाल ने ग्राम कमेलपुर में आयोजित जनसमस्या समाधान एवं जनसंवाद शिविरों में प्रतिभाग कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

कार्यक्रम के अंतर्गत उपाध्यक्ष ने रविदास मंदिर प्रांगण, कमेलपुर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने विधवा पेंशन, और राशन कार्ड सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कमेलपुर के इस शिविर में 19 शिकायतें एवं समस्याएं प्राप्त हुईं। इनमें सर्वाधिक राशन कार्ड से संबंधित थी। मौके पर उपस्थित



अधिकारियों द्वारा 08 समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार गांव, गरीब, किसान एवं जरूरतमंद नागरिकों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूर्णतः

प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों एवं जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने से राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ जनसमस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस में लगी आग, विदेशी नागरिक भी थे सवार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

देहरादून से दिल्ली जा रही निजी कंपनी की यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस में अचानक लगी आग से चीख पुकार मच गई। बस चालक ने किसी तरह बस को सड़क किनारे रोककर यात्रियों को सुरक्षित आग से बचाकर बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान आग से बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 4 बजे यह घटना हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर बहादुराबाद क्षेत्र में शांतराहा के पास हुई। निजी कंपनी की एसी बस देहरादून से जयपुर जा रही थी। बस में 32 यात्री सवार थे। जिनमें दो विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं। बस में अचानक आग लगने से यात्रीयों में अफरातफरी मच गयी। चालक परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोककर यात्रियों को नीचे उतारा। जिससे सभी की जान बच गयी और बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस



में आग लगने की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया। हालांकि तब तक बस आग का गोला बन चुकी थी और उसमें रखा यात्रियों का सामान भी जल कर राख हो चुका था। बस में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही इसकी पुष्टि होगी।



संपादकीय

रिजर्व बैंक ने खोली अर्थव्यवस्था के ढोल की पोल

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े विभिन्न संकेतक यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार और उसके समर्थकों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देने वाली वास्तविकताएं एक अलग कहानी कह रही हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है। एक समय देश अपनी जरूरत का लगभग 18 प्रतिशत कच्चा तेल और गैस स्वयं उत्पादित कर लेता था। शेष 82 प्रतिशत आयात करना पड़ता था। अब आयात पर निर्भरता और बढ़ गई है। कच्चे तेल, गैस, उर्वरक और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक सामान और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ता असंतुलन चिंता का विषय है। यदि किसी देश का आयात लगातार निर्यात से अधिक रहेगा तो अंततः विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। भारत का व्यापार घाटा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में वृद्धि दिखाई नहीं दे रही। जिस गति से आयात बढ़ा है, उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़ पाया है। इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ रहा है। डॉलर और युआन जैसी मुद्राओं के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। जिसके कारण आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। पिछले वर्षों में सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए, आलोचकों का मानना है, इन अभियानों का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में कहीं पर दिखाई भी दिए तो वो भी बहुत नीचे स्तर पर हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात आधारित उपभोग अर्थव्यवस्था को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता का एक दूसरा कारण देश में बढ़ता कर्ज है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार उधार लेकर खर्च बढ़ा रही हैं। निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। गोलड लोन, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड आधारित उधारी में तेजी से वृद्धि हुई है। जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास का आधार उत्पादन और आय की बजाय कर्ज बनने लगे, तो यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जाती। जब खर्च करने के लिये पैसे नहीं होंगे, तो आर्थिक विकास कैसे संभव है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है। इन तीनों घटनाओं ने छोटे और मध्यम उद्योगों को गहरा झटका दिया। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था, आज भी वह उबर नहीं पाया है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। लोगों की आय कई वर्षों से सीमित है। आय की तुलना में अधिक तेजी से जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है।

शेयर बाजार को लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बताया जाता रहा। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निकासी की जा रही है। यदि विदेशी निवेश कम होता है, घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता, तो आर्थिक विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर एशिया के कई शेयर बाजार अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल रही है। ऊर्जा आयात महंगा होता है, तो उसका असर परिवहन, कृषि, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पड़ता है। अंततः इसका भार आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। वर्तमान स्थिति की तुलना 1991 के आर्थिक संकट से होने लगी है। भारत के पास उस समय की तुलना में वर्तमान में कहीं अधिक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और विकसित वित्तीय बाजार मौजूद हैं। यह आशंका इस लिये व्यक्त की जा रही है, उस समय की तुलना में कर्ज और ब्याज का बोझ ज्यादा है। बढ़ता व्यापार घाटा, रोजगार संकट, महंगाई, सार्वजनिक ऋण और आयात पर बढ़ती निर्भरता ऐसे संकेत हैं, जिन्हें सरकार के लिये गंभीरता से स्वीकार करने की आवश्यकता है।

डिजिटल आक्रामकता के जाल में फंसा बचपन

दिलीप कुमार पाठक

आजकल घरों में शाम के वक्त एक खामोश नजारा दिखाई देता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में, एक ही सोफे पर साथ बैठा होता है, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती। सब के सब चुपचाप अपने-अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। माता-पिता भी इस बात से बड़े खुश और बेफिक्र रहते हैं कि उनका बच्चा बाहर धूप या धूल-मिट्टी में नहीं घूम रहा है, बल्कि घर के अंदर आराम से सुरक्षित बैठा है। लेकिन क्या कभी हमने ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचने की कोशिश की है कि स्क्रीन में अपनी आंखें गड़ाए बैठा हमारा यह मासूम बच्चा अंदर ही अंदर किस मानसिक दौर से गुजर रहा है? कहीं उसके नन्हें दिमाग पर नकारात्मक असर तो नहीं हो रहा?

हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पुराने जमाने में जब इस दिन की चर्चा होती थी, तो बच्चों पर अत्याचार का सीधा सा मतलब लड़ाई-झगड़े, युद्ध, दंगे या फिर फैक्ट्रियों में होने वाली बाल-मजूदारी से लगाया जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में मासूमों के खिलाफ होने वाली हिंसा का पूरा चेहरा ही बदल चुका है। अब यह आक्रामकता सड़क पर शोर नहीं मचाती। अब यह हिंसा बिना किसी आवाज के, इंटरनेट के महीन रास्तों से रंगती हुई सीधे हमारे घरों के भीतर और हमारे बच्चों के दिमाग पर सीधा हमला कर रही है। जरा रुककर गंभीरता से सोचिए। आपका बच्चा आपके ठीक सामने

बैठा हो सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ठीक उसी वक्त उसका कोमल मन किसी बहुत गहरे तनाव या डर में डूब रहा हो। ऑनलाइन गेम खेलते समय किसी अनजान शख्स द्वारा दी गई गंदी गालियां, सोशल मीडिया पर दोस्तों द्वारा उड़ायी गयी उसका कोई भद्दा मजाक, या फिर इंटरनेट के समंदर में छिपे किसी अपराधी की गंदी नजर। यह डिजिटल आक्रामकता ऐसी होती है जो बाहर से शरीर पर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके ज़ख्म और भी ज्यादा गहरे होते हैं। यह अदृश्य हमला बच्चे के आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। सबसे ज्यादा डरावना तो यह है कि इंटरनेट के इस गंदे खेल में कोई तीसरा देखने वाला गवाह नहीं होता, सिवाय उस एक सहमे हुए और अकेले पड़ चुके बच्चे के। वैश्विक संस्था यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर तीसरा इंसान असल में एक बच्चा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी ऑनलाइन किसी न किसी रूप में मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार होती है। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में बच्चों को रोने से रोकने या उन्हें शांत बैठाने के लिए खिलौने की जगह मोबाइल थमा देते हैं। यह डिजिटल झुनझुना शुरू-शुरू में तो हमें बड़ी राहत देता है, लेकिन धीरे-धीरे यही मोबाइल बच्चे और माता-पिता के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है। जब बच्चा इंटरनेट की किसी बड़ी मुसीबत या ब्लैकमेलिंग में फंसाता है, तो वह लोक-लाज और डर के मारे अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बता पाता।

कांग्रेस का पुनरुत्थान : दक्षिण भारत दिखा रहा है राह

प्रो. प्रदीप माथुर

इतिहास मानो स्वयं को दोहरा रहा है। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे, जनता पार्टी, से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। मात्र दो महीने पुरानी जनता पार्टी ने उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत में कांग्रेस जैसी पुरानी और स्थापित पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था। लेकिन दक्षिण भारत इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा और कांग्रेस के पुनरुत्थान का उत्प्रेरक बना। परिणामस्वरूप, सत्ता खोने के मात्र तीन वर्षों के भीतर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में लौट आई।

क्या अब एक बार फिर दक्षिण भारत कांग्रेस के पुनरुत्थान का उत्प्रेरक बनने जा रहा है और उसे नई दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा?

निस्संदेह, इस बार परिस्थितियाँ काफी भिन्न हैं। अब लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि एक हानिकारक वैचारिक तंत्र के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसी क्षमता और करिश्मे वाला कोई नेता भी नहीं है।

यह सच है कि मोदी सरकार जैसी मजबूत और जमी हुई सत्ता को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास इंदिरा गांधी के कद का नेता नहीं है। किंतु उसके पास अपार संभावनाओं वाले कई नेता हैं। इनमें नवीनतम नाम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति का है, जिनकी मात्र दो वर्ष पुरानी टीवीके (ज़ड्डूच्य) पार्टी लगभग आधी सदी पुरानी सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल के तीव्र चुनावी संघर्ष और विदेश में खाड़ी युद्ध जैसी घटनाओं के बीच हम राष्ट्रीय राजनीति पर विजय थलापति की जीत के प्रभाव का सही आकलन नहीं कर पाए हैं। इसे किसी दूरस्थ दक्षिणी राज्य की एक छोटी घटना मानना बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें केवल एक

लोकप्रिय फिल्म स्टार मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्हें तमिलनाडु के फिल्म-प्रेमी लोगों ने उसी प्रकार सत्ता में पहुंचाया हो जैसा उन्होंने करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता के मामले में किया था।

विजय वैचारिक रूप से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं, इससे पहले कि मोदी ने भारतीय राजनीति के संतुलन को बदलकर उसे हिंदुत्व और पूंजीपति-परस्त व्यवस्था की ओर मोड़ दिया।

विजय खुलकर धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गरीब-समर्थक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जो मोदी की भाजपा और उसके कॉर्पोरेट समर्थकों को स्वीकार्य नहीं है। जब अनेक नेता बहुसंख्यक समुदाय के समर्थन के खोने के भय से धर्मनिरपेक्षता की बात करने से कतराते हैं, तब विजय ने ऐसी कोई झिझक नहीं दिखाई है। वे भारतीय धर्मनिरपेक्ष परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उभरे हैं—एक ईसाई, जो मात्र 6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन जिन्हें 88 प्रतिशत हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने अपना नेता चुना है।

कांग्रेस की विचारधारा के प्रति विजय का समर्थन और राहुल गांधी के प्रति उनकी प्रशंसा किसी से छिपी नहीं है। जहाँ उत्तर भारत के भाजपा-विरोधी नेता, जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के प्रति सावधानीपूर्ण रख अपनाते रहे हैं, वहीं विजय ने ऐसा कोई संकोच नहीं दिखाया। लगभग 50 वर्षों में पहली बार कांग्रेस तमिलनाडु की सत्तारूढ़ व्यवस्था का हिस्सा बनी है।

यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ अपने गठबंधन में पूरी तरह सहज नहीं हैं। उन्हें आशंका है कि मोदी की भाजपा से उनकी निकटता मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनके समर्थन को नुकसान पहुंचा सकती है, जो लंबे समय से उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा, चंद्रबाबू नायडू महत्वाकांक्षी नेता हैं और

आगामी दिनों में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के मायने

सौरभ वाष्पण्य

भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों के मंच के रूप में उभरे इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक पर देश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं। यह बैठक केवल विभिन्न दलों के नेताओं का एक औपचारिक जमावड़ा नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकता, उसकी रणनीति और भविष्य की राजनीतिक दिशा का महत्वपूर्ण संकेतक भी मानी जा रही है। ऐसे समय में जब देश की राजनीति लगातार नए समीकरणों और चुनौतियों से गुजर रही है, यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि विपक्ष यदि एकजुट होकर रणनीति बनाए तो वह सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन के भीतर कई मुद्दों पर मतभेदों की चर्चाएं भी सामने आईं। ऐसे में यह बैठक गठबंधन के भीतर विश्वास और समन्वय को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

बैठक का एक प्रमुख एजेंडा संसद के आगामी सत्रों में विपक्ष की संयुक्त रणनीति तय करना हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर विपक्ष किस प्रकार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, इस पर चर्चा होने की संभावना है। यदि गठबंधन इन मुद्दों पर एक स्वर में बोलने में सफल रहता है तो उसकी राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ सकती है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव भी बैठक के केंद्र में रह सकते हैं। सीटों के तालमेल, चुनावी रणनीति और साझा प्रचार अभियान जैसे विषयों पर सहमति बनाना गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। कई राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी रहे हैं। इसलिए यह बैठक इस बात की भी परीक्षा होगी कि गठबंधन अपने आंतरिक मतभेदों को

कितनी कुशलता से संभाल पाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह बैठक विपक्षी नेतृत्व के प्रश्न पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि देश के सामने एक वैकल्पिक दृष्टि और भरोसेमंद नेतृत्व प्रस्तुत करना भी है। जनता केवल विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि समाधान और सकारात्मक एजेंडा भी देखना चाहती है।

सत्तापक्ष के लिए भी इस बैठक के निहितार्थ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक मजबूत और संगठित विपक्ष लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाता है। विपक्ष की सक्रियता सरकार को अपनी नीतियों और निर्णयों पर अधिक स्पष्टता तथा जवाबदेही के लिए प्रेरित करती है। इसलिए विपक्षी एकता का प्रश्न केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का भी विषय है।

इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक का महत्व उसके द्वारा पारित प्रस्तावों से कहीं अधिक इस बात में निहित होगा कि वह जनता के बीच कितना विश्वास पैदा कर पाती है। यदि बैठक से स्पष्ट रणनीति, मजबूत समन्वय और जनहित के मुद्दों पर ठोस दृष्टिकोण सामने आता है, तो यह विपक्ष के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। लेकिन यदि मतभेद और अस्पष्टता हावी रहती है, तो गठबंधन के सामने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती और बढ़ जाएगी। लोकतंत्र में सशक्त सरकार जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष भी है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक इसी कसौटी पर परखी जाएगी।

इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक केवल सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति या सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहने वाली है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ (टीएमसी) से जुड़े नेताओं पर हुए हमलों, पार्टी और सहयोगी दलों के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी तथा

राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।

कर्नाटक, तेलंगाना और केरल पहले से ही कांग्रेस के प्रभाव या नियंत्रण में हैं और तमिलनाडु में भी एक मित्रवत मुख्यमंत्री है। ऐसे में कांग्रेस का पुनरुत्थान धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से दक्षिण भारत से शुरू होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था।

निस्संदेह, इस बार संघर्ष अधिक कठिन है, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को केवल एक अत्यंत कुशल और चालाक नेता तथा उसकी पार्टी से ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक विचारधारा, विशाल धनबल, सरकारी मशीनरी के खुले उपयोग, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के हनन और एक अनुकूल मीडिया से भी मुकाबला करना पड़ रहा है।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियाँ हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बदल रही हैं। भाजपा भले ही चुनाव जीत रही हो, लेकिन वह लगातार जनसमर्थन खो रही है। अब जनता भी धर्म के नशे से धीरे-धीरे बाहर निकल रही है।

बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों को भाजपा और उसके वादों से निराश कर दिया है। जनरेशन-जेड (तदृष्ट) विशेष रूप से नाराज है, जैसा कि नीट (हृष्यध्वज) परीक्षा-पत्र लीक प्रकरण पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया और 'कॉकरोच जनता पार्टी' को मिले व्यापक समर्थन से देखा जा सकता है।

चेन्नई में विजय थलापति का सत्ता में आना अकेले भाजपा जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे अकेले भी नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी भी हैं, जिनमें दक्षिण भारत के बहुत से लोग, विशेषकर महिलाएँ, अपनी प्रिय 'इंदिरा अम्मा' की छवि देखती हैं। प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही केरल की वायनाड सीट जीतकर की है।

विपक्षी एकजुटता को लेकर उठ रहे सवालों के कारण टीएमसी का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है।

टीएमसी इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है। पश्चिम बंगाल में उसका मजबूत जनाधार है और राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। लेकिन कई अवसरों पर टीएमसी और गठबंधन के अन्य दलों, के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यदि विपक्षी एकता को मजबूत करना है तो इन अंतर्विरोधों पर खुलकर चर्चा आवश्यक होगी।

हाल ही में टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि किसी दल के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगता है, तो यह केवल उस दल का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का विषय बन जाता है। इसलिए संभावना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राजनीतिक हिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा भी उठे। दूसरी ओर, गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के मुकाबले एक साझा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की है। यदि सहयोगी दल आपसी मतभेदों को सार्वजनिक रूप से बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा लाभ सत्तापक्ष को मिल सकता है। इसलिए बैठक में टीएमसी से जुड़े विवादों पर चर्चा होने के साथ-साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी गठबंधन केवल चुनावी गणित का नाम नहीं है। उसकी सफलता आपसी विश्वास, साझा कार्यक्रम और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। टीएमसी का मुद्दा यदि बैठक में उठता है तो उसका उद्देश्य किसी दल को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि गठबंधन की एकजुटता और विश्वसनीयता को मजबूत करना होना चाहिए।

एक नजर

शासन ने प्रदेश के सात जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के किये तबादले

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अल्मोड़ा समेत सात जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के तबादले और नई नियुक्तियों की हैं। स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में नए सीएमओ की तैनाती की गई है। उत्तराखंड में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण कई बार स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और व्यवस्थागत कमियां सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जारी आदेश के अनुसार डॉ. योगेश पुरोहित को अल्मोड़ा, डॉ. रश्मि पंत को नैनीताल, डॉ. हरीश चन्द्र पंत को पिथौरागढ़, डॉ. मेघना असवाल को पौड़ी, डॉ. अमित कुमार शुक्ला को रुद्रप्रयाग, डॉ. राम प्रकाश को टिहरी तथा डॉ. श्याम विजय को उत्तरकाशी जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन नियुक्तियों को अमल में लाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए अधिकारियों के नेतृत्व में संबंधित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को समयबद्ध एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चिकित्सा संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और जनस्वास्थ्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए सीएमओ अपने-अपने जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, अस्पतालों की निगरानी तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हरिद्वार में होगा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. स्वास्तिक सुरेश जैन ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हरिद्वार को चयनित किया गया है तथा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डॉ. सुरेश ने बताया कि योग दिवस के अंतर्गत योग पार्क की स्थापना, 'हरित योग', 'रन फॉर योग' सहित कई विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न चयनित स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने जनपदवासियों एवं देशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि नियमित योग से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने सभी लोगों से 21 जून को योग दिवस कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने गेट सिस्टम को बताया प्रभावी पहल

पथ प्रवाह, चमोली। श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चमोली पुलिस द्वारा ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी के मध्य गेट सिस्टम प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत निर्धारित समयानुसार वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा रही है, जिससे यात्रा मार्ग पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और श्रद्धालुओं को निर्बाध यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके। गेट सिस्टम लागू होने के बाद यात्रा मार्ग पर यातायात संचालन अधिक सुव्यवस्थित हुआ है तथा वाहनों का दबाव नियंत्रित रहने से श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा और जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं एवं आवश्यक वाहनों की आवाजाही भी अधिक सुचारू रूप से संचालित हो रही है। स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों ने भी इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि गेट सिस्टम लागू होने से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है व स्थानीय व्यवसायों को भी सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ है तथा बाजार क्षेत्र में आवाजाही अधिक व्यवस्थित हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चमोली पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था यात्रा सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है।

अंडमान गैंगरेप मामले में बड़ा मोड़, चार गवाह अदालत में मुकरे

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण से जुड़े चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के चार अहम गवाह अदालत में अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष को झटका लग सकता है। यह मामला वर्ष 2022 में सामने आया था, जब एक युवती ने आरोप लगाया था कि उसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के आवास पर बुलाया गया और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में तत्कालीन श्रम आयुक्त आर. एल. ऋषि और व्यवसायी संदीप सिंह उर्फ रिंकू सहित अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। ताजा सुनवाई के दौरान चार गवाहों ने अदालत में अपने पूर्व बयानों का समर्थन नहीं किया और उन्हें 'शत्रुतापूर्ण गवाह' (होस्टाइल विटनेस) घोषित किया गया। ऐसे मामलों में गवाहों के बयान बदलने से मुकदमे की दिशा प्रभावित हो सकती है, हालांकि अभियोजन पक्ष अन्य साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करेगा। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। वहीं, पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताते रहे हैं।

जन्म से शिक्षा तक बच्चों की होगी डिजिटल ट्रेकिंग, एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रदेश में बच्चों के समग्र विकास और उनकी शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी प्रगति की निगरानी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की जन्म से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक की पूरी जानकारी के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए।

उन्होंने सभी बच्चों के लिए आभा और अपार आईडी बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन माध्यमों से बच्चों की ट्रेकिंग को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे बच्चे के जन्म के साथ ही टीकाकरण, आंगनबाड़ी में प्रवेश, विद्यालय में नामांकन और शैक्षणिक उपलब्धियों तक का पूरा डाटा एक ही जगह उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सिस्टम के माध्यम से अभिभावकों को समय-समय पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएं, जिससे उन्हें टीकाकरण या स्कूल में प्रवेश जैसी आवश्यक जानकारी समय पर मिल सके। साथ ही संबंधित विभाग भी बच्चों का नियमित फॉलोअप कर सकें। मुख्य सचिव ने



इस दिशा में सभी संबंधित विभागों, एनआईसी और आईटीडीए के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र कार्य योजना तैयार करने और जल्द ही पुनः समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव रविनाथ रमन, विनय शंकर पाण्डेय, सी. रविशंकर, अपर सचिव सुश्री रीना जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सिंगल विंडो बैठक में निवेश प्रस्तावों को मिली संस्तुति, देरी पर मुख्य सचिव सख्त

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु डीजी एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर लैंड यूज चेंज (धारा 143) एवं अन्य संबंधित मामलों (धारा 154) के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो से जुड़े मामलों का प्रोएक्टिव होकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने सचिव उद्योग को भी निर्देशित किया कि लंबित मामलों में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिंगल विंडो के अंतर्गत दी जाने वाली सभी स्वीकृतियां निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रथम एवं



द्वितीय चरण के सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षण्मुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकारे, अपर सचिव सोरभ गहवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में युवाओं की सहभागिता के लिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का शुभारंभ

पथ प्रवाह, देहरादून।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीवीपी) 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुल 500 'एमवाई भारत' स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। इनका चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इस महीने के अंत में 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे।

यह कार्यक्रम युवा नागरिकों को सीमावर्ती गांवों में रहने और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने का एक अनूठा

अवसर प्रदान करता है। गांववासियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से, प्रतिभागी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक विरासत, विकासवात्मक आकांक्षाओं और रणनीतिक महत्व से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होंगे।

सात दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीमा जागरूकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सामुदायिक जीवन, शासन, सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन, ग्राम विकास योजना, स्वयंसेवा और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयगत क्षेत्रों के ईर्द-गिर्द संरचित किया गया है। स्वयंसेवक घरेलू सर्वेक्षण करेंगे, ग्राम सभा की गतिविधियों में भाग लेंगे, स्वच्छता और पर्यावरण अभियानों में योगदान देंगे और गांवों में विकास के अवसरों की पहचान करने में सहायता करेंगे। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'नेशन फर्स्ट चैलेंज' का प्रचार-प्रसार है, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और जिम्मेदार नागरिकता एवं टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देता है। एमवाई भारत के स्वयंसेवक इस अभियान के पांच प्रमुख विषयगत क्षेत्रों : स्वदेशी उत्पादों का अंगीकरण, स्वस्थ खाना पकाने की विधियाँ, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और ईंधन संरक्षण, प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देना और स्थानीय पर्यटन के लिए मुखर समर्थन की सक्रिय रूप से सहायता करेंगे। सामुदायिक

संपर्क और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से, प्रतिभागी स्थानीय समुदायों को इन राष्ट्र-केन्द्रित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण की पहलों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना के अनुरूप है।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। माय इंडिया, आईटीबीपी, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए समन्वय तंत्र स्थापित किए गए हैं। सुचारू क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए समर्पित नियंत्रण कक्ष, नोडल अधिकारी, ग्राम कार्य योजनाएं, प्रतिभागी अभिविन्यास सत्र और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं।

विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 भारत सरकार की युवा नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, भारत के युवाओं और इसके जीवंत सीमावर्ती गांवों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासवात्मक संबंधों को सुदृढ़ करता है।



विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

बैठक में बताया गया कि 29 मई से 7 जून 2026 तक प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग कार्य संपन्न किया जाएगा। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई



तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन एवं गणना प्रपत्र भरने का कार्य करेंगे। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 07 जुलाई तक तथा मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 14 जुलाई तक किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक तथा नोटिस चरण/दावों का

निपटान एवं आपत्ति 14 जुलाई से 11 सितंबर तक व अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मृत, स्थानांतरित, अपात्र एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर सूची को अधिक विश्वसनीय एवं अद्यतन

बनाना है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि एन्यूमरेशन चरण के दौरान किसी प्रकार के दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा किसी कारण से हट गया है, तो वह प्रारूप-6 एवं घोषणा पत्र के माध्यम से अपना

नाम पुनः दर्ज करा सकता है। प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने कार्यकर्ताओं एवं बीएलए के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को एसआईआर अभियान के प्रति जागरूक करने तथा बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की, ताकि अभियान को निष्पक्ष, प्रभावी एवं त्रुटिरहित ढंग से पूरा किया जा सके।

बैठक से पूर्व जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का रूटीन निरीक्षण भी किया गया।

बैठक में बीजेपी से मनोज सिंह, कांग्रेस से दिनेश गौड़, प्रदीप सिंह सुधीश पंवार, बीएसपी से बुद्धिलाल, आप से दीपक चन्द रमोला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश मोहन राणा सहित अन्य उपस्थित रहे।

एक नजर

भाजयुमो के स्वागत समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक



पथ प्रवाह, हरिद्वार। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नव नियुक्त मंडल पदाधिकारियों के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, जिसकी शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा के नव नियुक्त पदाधिकारी संगठन की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और समर्पण ही संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यक्रम में उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान नव नियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा एवं युवा मोर्चा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिनव चौहान, मंडल अध्यक्ष करन वर्मा, हिमांशु वर्मा, आलोक पाण्डेय, ईशांत उपाध्याय, अनिल वशिष्ठ, दीपांशु विद्यार्थी, भोला शर्मा, प्रशांत घाघट, शिवम ठाकुर, राघव चौहान, संदीप भट्ट आदि उपस्थित रहे।

एसएसपी अजय गणपति के सख्त रुख से अपराधियों में खौफ, जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, उधमसिंह नगर। लगातार फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार युवक ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी जीभ काट ली थी। पुलिस के मुताबिक 10 अप्रैल 2026 को रम्पुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर राजू पुत्र जागन, जितेन्द्र पुत्र जागन, जितेन्द्र पुत्र बादाम सिंह, सचिन पुत्र कुंवरपाल तथा जीत पुत्र जगदीश निवासीगण रम्पुरा, थाना रुद्रपुर द्वारा राज कोली पुत्र स्वर्गीय वीरपाल निवासी रम्पुरा पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले के दौरान आरोपियों ने अत्यंत क्रूरता का परिचय देते हुए राज कोली की जीभ काट दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में कोतवाली रुद्रपुर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस



अधीक्षक ऊधम सिंह नगर अजय गणपति द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। फरार आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी प्राप्त किए गए। लगातार प्रयासों के क्रम में पुलिस ने पता लगाया कि घटना का मुख्य आरोपी जितेन्द्र पुत्र जागन लाल रम्पुरा क्षेत्र में मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है।

फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1-द हार्ट की टीम ने लिया संतों से आशीर्वाद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1-द हार्ट की टीम ने हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचकर देश के प्रतिष्ठित संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिल्म के मुख्य अभिनेता देहरादून निवासी सिद्धार्थ गुप्ता, फिल्म में सत्यभामा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री संस्कृति जयाना और निर्माता साजन राज कुरूप के साथ फिल्म की टीम हरिद्वार पहुंची और योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी तथा परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी संतों ने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने के प्रयास की सराहना की। देहरादून में जन्मे और पले-बढ़े सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है।



उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार में गंगा स्नान और गंगा आरती में भाग लेना बेहद सुखद और यादगार रहा। टीम ने हरिद्वार और ऋषिकेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए और फिल्म की

सफलता के लिए प्रार्थना की। निर्माता साजन राज कुरूप ने बताया कि कृष्णावतारम पार्ट-1 द हार्ट जैसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित फिल्म के लिए संतों का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दर्शकों द्वारा फिल्म को मिल रहे प्रेम और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक भूमिका निभाएगी सपा-महंत शुभम गिरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन शहर कार्यालय पर किया गया। बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डा.सत्यनारायण सचान व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी ने उत्तराखंड में मूल निवास और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करते हुए पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी ने कहा कि जनसमस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाएं। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करें। उन्होंने कहा कि सपा जल्द ही उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक भूमिका निभाएगी। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष यादव व सपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित सुमित तिवारी ने उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से



बढ़कर 27 करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया है। जिस कारण ओबीसी वर्ग को संविधान से प्राप्त आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैठक में श्रम सभा के

जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव, समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीक्षांत शर्मा, उपाध्यक्ष आदेश उपाध्याय, आस्तिक यादव, रिकू, बंटी, पवन कुमार, शिबू कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीएमओ से मिला इएमए का प्रतिनिधिमंडल

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

इएमए के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.आरके सिंह से मिलकर राजा गार्डन जगजीतपुर में सील किए गए इंच प्रेक्विशनर रमेशचंद्र जालान के क्लीनिक को तत्काल खोलने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वस्तु स्थिति एवं राज्य सरकार द्वारा प्रेक्विटस के संदर्भ में जारी शासनादेश से अवगत कराते हुए कहा कि तथ्यों व जानकारी न होने के कारण एसीएमओ द्वारा इंच क्लीनिक को सील कर दिया गया है। जिसे तत्काल खोला जाए। इएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.केपीएस चौहान ने सीएमओ से फोन पर वार्ता कर अवगत कराया



कि इंच चिकित्सक के खिलाफ की गयी सीलिंग की कार्यवाही राज्य एवं केन्द्र सरकार के शासनादेश की अवहेलना तथा उच्च

न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना के दायरे में आता है। डा.चैहान ने यह भी कहा कि इलेक...



संकट का सामना कर रहे खेती और किसान-धर्मेश सिंह

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अलकनंदा मैदान पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अधिवेशन में खेती किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार से किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग की गयी। इस दौरान संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गयी। अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश सिंह ने कहा कि खेती और किसान दोनों संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार को किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में खाद की कमी, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी के चलते किसान गहरे आर्थिक दबाव में हैं। गन्ना मित्तों पर बकाया भुगतान के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। धर्मेश सिंह ने कहा कि किसानों की



समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। आयोग में किसान संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 20 हजार

वार्षिक किया जाए। किसानों को दो लाख रूपए तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सभी फसलों

को एमएसपी की गारंटी के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। किसानों की तरक्की के लिए

केंद्र व राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाने चाहिए। कहा कि किसानों के हितों के लिए भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ला, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डा.नरपाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीके सिंह, कृष्ण कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान, राष्ट्रीय सलाहकार तिलकराज वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विनेश तिवारी, अमित वैष्णव, सुधीर चौधरी, विपुल चौधरी, कविता राणा, गुर्दीप कौर, विजय गायल, अक्वीश सिंह, अनिल कन्नौजिया, आशीष सिंह, जोगेंद्र चौधरी, वीर बहादुर सिंह, अबरार, प्रवीण तोमर, नागेंद्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार, वीरेंद्र गिल, धीरेंद्र परिहार, मुकेश गौतम, सचिन चौधरी, आद्या प्रसाद मिश्रा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे।

एक नजर

एचआरडीए ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी पर चलाया बुलडोजर



पथ प्रवाह, हरिद्वार। रुड़की के नया बाईपास बेल्टा पेट्रोल पम्प के पीछे अजय सेनी द्वारा लगभग 30 से 40 बीघा के क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। प्राधिकरण द्वारा उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद योजित किया गया है। स्थल पर निरंतर निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य बंद ना करने के कारण प्राधिकरण टीम द्वारा अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया तथा मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य ना किया जाने के लिए निर्देशित किया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं के लिए सुपर स्पेशलिस्ट सेवा शुरू

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिली है। संस्थान में पहली बार नियोनेटोलॉजी (नवजात चिकित्सा) के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती की गई है, जिससे गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को अब स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो सकेगा। संस्थान के प्राचार्य डॉ. चंद्र प्रकाश भैसोड़ा के प्रयासों से बाल एवं नवजात शिशु विभाग में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार सिंह ने बताया कि नवजात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. सुमित जीना ने 1 जून से सह प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वहीं डॉ. ज्योति कांडपाल पहले से विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग में छह विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बाह्य एवं अंतः रोगी सेवाओं, नवजात एवं बाल गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू/पीआईसीयू), टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है। विभाग में 22 शैय्याओं वाली गहन चिकित्सा इकाई संचालित है। डॉ. सिंह ने बताया कि नए विशेषज्ञों की नियुक्ति के बाद विभाग की सेवाओं के विस्तार की योजना भी तैयार की गई है। इससे उपचार क्षमता बढ़ेगी और गंभीर नवजात शिशुओं तथा जटिल बाल रोगों के इलाज में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से अल्मोड़ा ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ सेवाओं और गहन चिकित्सा इकाइयों के विस्तार से नवजात एवं बाल चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम करने में भी मदद मिलेगी। डॉ. अमित कुमार सिंह ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से नवजात एवं बाल रोग संबंधी समस्याओं के लिए इन विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की।

बेस अस्पताल में अतिरिक्त पंजीकरण काउंटर शुरू

मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के अधीन बेस चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए 1 जून से ओपीडी ब्लॉक-2 में अतिरिक्त पंजीकरण काउंटर भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे मरीजों को भीड़ और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। चिकित्सा अधीक्षक ने लोगों से ऑनलाइन पर्ची प्रणाली का भी अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

कार से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने सीज की कार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कार से खतरनाक स्टंट कर वीडियो बनाना चालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए वाहन को भी सीज कर दिया। कार व बाइक आदि से खतरनाक स्टंट पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भेल स्टैंडियम के पास एक कार चालक द्वारा स्टंट किए जाने के वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर कोतवाली पुलिस ने कार की पहचान कर चालक साजिद पुत्र फुरकान निवासी एक्कड़ खुर्द को हिरासत में लेने के साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कारवाई करते हुए कार को सीज कर दिया।



वन पंचायतों में गैर काष्ठीय वन उपज और हर्बल पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

जनपद की वन पंचायतों में गैर काष्ठीय वन उपज के विकास तथा हर्बल एवं अरोमा पर्यटन परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने संबंधित विभागों को क्लस्टर आधारित मॉडल पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से ग्रामीणों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर सृजित किए जाएं। मंगलवार को आयोजित क्लस्टर स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायतों का चयन और गतिविधियों का संचालन ऐसी योजना के तहत किया जाए, जिससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और अधिकतम लोगों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध वन संपदा तथा औषधीय एवं सगंध पौधों की प्रचुरता को स्थानीय आर्थिक विकास से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना को परिणामोन्मुख और जनहितकारी बनाना होगा। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बैठक में



प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि गैर काष्ठीय वन उपज विकास तथा हर्बल एवं अरोमा पर्यटन परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य वन पंचायतों में औषधीय और सगंध पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना वर्ष 2023-24 से शुरू की गई है और वर्ष 2033-34 तक संचालित रहेगी। योजना केवल वन

पंचायतों में लागू होगी, जहां विभिन्न विभाग तकनीकी और अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। परियोजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों का संचालन स्थानीय समुदाय और वन पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल सकेगा। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप धौलाखंडी, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली के मालवीय नगर होटल में अग्निकांड! अब 21 की मौत; 47 लोगों का किया रेस्क्यू

नई दिल्ली। राजधानी के दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी इलाके में स्थित फ्लोरिस्ट इन होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कम से कम 21 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। सुबह 8.50 बजे सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक 47 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, जबकि पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास में रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि 5 मंजिला

इस होटल में 25 कमरे बने हुए थे, जिसमें 40 लोग रुके हुए थे। इसमें ज्यादातर विदेशी लोग शामिल थे जो बाहर से इलाज कराने के लिए आए थे। जब होटल में आग लगी थी तब ज्यादातर लोग सोए हुए हुए थे। मरने वाले सभी लोग विदेशी बताए जा रहे हैं। हौजरानी की तंग गलियों में बने इस होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट बना हुआ था। होटल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ केसर सिंह ने पुलिस को बताया कि सुबह का वक्त था करीब 8 बजे जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक चूल्हे को जलाने की कोशिश की तो आग एक दम भड़क गई। आग पहले से होटल में लगी थी मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बोला कि होटल में आग लगी है। मैं बाहर आया तो देखा कि होटल जल रहा था।

मैं किसी तरह वहां से बचकर निकला। खुद केसर नेगी बताते हैं कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो सकती है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, तो वहीं अग्निशमन अधिकारी एके मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 8:50 बजे हमें कॉल मिली थी। शुरुआत में 7 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया, उसके बाद और गाड़ियों को भेजा गया...37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इमारत को पूरा सर्व कर लिया गया है... इस बीच मालवीय नगर में आग लगने की जगह पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए पहुंची है।



मेलाधिकारी ने सीसीआर-2 भवन एवं घाटों के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, निर्माण सामग्री के नमूने लेकर जांच को भेजने के लिए निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कुंभ मेला-2027 के सफल आयोजन के लिए संचालित अवस्थापना विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु मेला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का गहन जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी परियोजनाओं को तय समयवाधि में पूर्ण किया जाए।

मेलाधिकारी ने सर्वप्रथम सीसीआर-2 भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों से परियोजना की चरणबद्ध प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए



निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला-2027 की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसके निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त

ईट, सीमेंट एवं अन्य सामग्री के नमूने मौके पर ही एकत्र करवाए।

इसके उपरांत मेलाधिकारी ने गंग नहर के बाएं तट पर शहीद भगत सिंह घाट से सिंह द्वार के मध्य निर्माणाधीन नए घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में प्रयुक्त स्टील, कंक्रीट एवं अन्य सामग्रियों

के नमूने जांच हेतु एकत्र करवाए। साथ ही घाट की नवनिर्मित आरसीसी दीवार के कुछ हिस्सों के नमूने भी गुणवत्ता परीक्षण के लिए निकलवाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा गुणवत्ता संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मेलाधिकारी ने नगर निगम घाट एवं उससे सटे क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने घाटों की दीवारों के स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराने तथा समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेला-2027 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने घाट क्षेत्रों में हरित विकास, सौंदर्यीकरण तथा सुगम

आवागमन की सुविधाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराना मेला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही या देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य में यदि किसी कारणवश कोई बाधा आ रही है तो उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका शीघ्र समाधान कर निर्माण कार्यों की प्रगति को निर्बाध बनाए रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान तकनीकी सेल के अधीक्षण अभियंता डी.पी. सिंह, पीआईयू के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुश, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अनुभव नौटियाल, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के सहायक अभियंता मानेंद्र पंवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

गाय को माता मानने की परंपरा आस्था से जुड़ी है, सरकारी घोषणा की मोहताज नहीं : जमाल सिद्दीकी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ धर्मगुरु, मुफ्ती-मौलवी और स्वयंभू बुद्धिजीवी यह तर्क दे रहे हैं कि गाय को पहले राष्ट्रीय पशु अथवा राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तभी उसे माता माना जाना चाहिए। यह तर्क भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक भावनाओं की मूल भावना को समझने में विफल प्रतीत होता है। मेरा उनसे सवाल है कि राष्ट्रपिता मोहन दास करमचंद गांधी को किस संवैधानिक प्रावधान या कानून के तहत आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता घोषित किया गया था, जिसके बाद पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगा?

सत्य यह है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का सम्मान किसी संवैधानिक घोषणा से नहीं, बल्कि देश की जनभावना, उनके योगदान और सामाजिक स्वीकृति से मिला। उसी प्रकार अनेक लोग गाय को धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक आधार पर गौमाता मानते हैं 7 किसी व्यक्ति, प्रतीक या परंपरा के प्रति सम्मान हमेशा सरकारी अधिसूचना या संवैधानिक दर्जे का मोहताज नहीं होता। समाज कई बार अपने आदर्शों और आस्थाओं के आधार पर भी सम्मानसूचक संबोधन देता है। गाय को गौमाता मानने की परंपरा भी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, कृषि-आधारित जीवन पद्धति और लोक आस्था से जुड़ी हुई है।

जमाल सिद्दीकी ने कहा कि देश के करोड़ों लोग गाय को मातृवत सम्मान देते हैं। यह उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का विषय है, जिसका सम्मान लोकतांत्रिक समाज में किया जाना चाहिए। किसी समुदाय की आस्था को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे किसी विशेष कानूनी या संवैधानिक उपाधि का दर्जा प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न धर्मों, परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान हमारी सद्भावावस्था का हिस्सा है। ऐसे में समाज को विभाजित करने वाले अनावश्यक विवादों से बचते हुए आपसी सद्भाव, संवाद और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि गाय केवल आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है। गाय के दूध से करोड़ों किसानों, पशुपालकों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है, जिसमें गाय आधारित डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए गाय का महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पोषण संबंधी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और किसान कल्याण में गाय का योगदान निर्विवाद है। इस्लाम में गाय का दूध अल्लाह की महान नेमतों में से एक माना गया है। पवित्र कुरआन में दूध को एक शुद्ध, पौष्टिक और लाभदायक पेय बताया गया है, जो इंसानों के लिए अल्लाह की रहमत का प्रतीक है। गाय दूध के माध्यम से इंसान को अल्लाह की कुरदरत और रहमत का एहसास होता है।

ममता को बड़ा झटका, ऋतब्रत बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व वाले बागी गुट को मान्यता देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह घटनाक्रम टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऋतब्रत बनर्जी और उनके समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को 58 से अधिक विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे हैं। बागी गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता और अन्य नेताओं को प्रमुख पदों पर नामित करने का प्रस्ताव भी दिया है। टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित कार्यालय आधिकारिक रूप से आवंटित कर दिया गया है और ऋतब्रत बनर्जी ने वहां कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बागी गुट अब विधानसभा के भीतर प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायकों ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी चेरपरसन बताया है। इससे संकेत मिलता है कि उनका विरोध सीधे ममता बनर्जी के बजाय वर्तमान संगठनात्मक नेतृत्व और सत्ता संरचना को लेकर है। संदीपन साहा ने पार्टी को मौजूदा स्थिति के लिए अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि पार्टी की उपलब्धियों का श्रेय नेतृत्व को मिलता है तो संगठन में पैदा हुई समस्याओं की जिम्मेदारी भी नेतृत्व को लेनी चाहिए।

'बारह साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' अभियान को सफल बनाने का आह्वान

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले 'बारह साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का आह्वान किया है। इस संबंध में बुधवार को पातालदेवी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महेश नयाल, मुख्य वक्ता बसंत जोशी, पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, कैलाश शर्मा तथा निवर्तमान जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी अभियान के तहत कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। मुख्य वक्ता बसंत जोशी ने कहा कि संगठन की शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता, आधारभूत ढांचे के विकास और वैश्विक स्तर



पर प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अभियान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि 5 जून से 21 जून तक जिला, विधानसभा, ब्लॉक और मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान, जनसंपर्क अभियान, स्वच्छता अभियान, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, प्रदर्शनी, जनकल्याण शिविर, प्रबुद्धजन बैठकें, प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशालाएं तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण अभियान के जिला संयोजक जिला महामंत्री दर्शन रावत रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला

महामंत्री प्रकाश भट्ट और दर्शन रावत ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में ब्लॉक प्रमुख हिमानी कुंडू, नीमा आर्या, प्रदेश उपाध्यक्ष किरण पंत, मनीष जोशी, ललित लटवाल, रवि रौतेला, विनीत बिष्ट, संजय बिष्ट, नवीन बिष्ट, मंगल सिंह, हरीश सिजवाली, दिनेश पांडे, जगदीश रावत, संदीप श्रीवास्तव, सुनील बिष्ट, मदन बिष्ट, नरेंद्र आगरी, महिपाल बिष्ट, गोविंद मटेला, हरीश कनवाल, आनंद डंगवाल, कैलाश गोस्वामी, पूनम पालीवाल, कविता शाह, वंदना आर्या, नमन गुरुरानी, पंकज भाकूनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

साल 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार : कुमारी शैलजा

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने राहुल गांधी के 4 जून को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद बताया। बुधवार को अल्मोड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुमारी शैलजा ने बताया कि राहुल गांधी अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत अल्मोड़ा से करेंगे, जहां एक जनसभा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में उत्साह का माहौल है। उन्होंने बताया कि दौरे के पहले दिन अल्मोड़ा में जनसभा के अलावा पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद तथा कोटद्वार में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरे दिन देहरादून में राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल से



निराश है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष है तथा पलायन, पर्यटन, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं, वनाग्नि, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे अधिक असर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है। कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच लगातार उठा रही है तथा सदन में भी

प्रमुखता से रख रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने दावा किया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है और वर्ष 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व स्पीकर गोविन्द सिंह कुंजवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, करन माहरा आदि मौजूद रहे।